



**J. Alam**  
**Joint Secretary (EE-I)**  
**Tele. No. 011-23384245**  
**Telefax: 011-23073736**  
**Email : [jalam.edu@nic.in](mailto:jalam.edu@nic.in)**

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
शास्त्री भवन  
नई दिल्ली - 110 115  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY  
SHASTRI BHAVAN  
NEW DELHI-110 115

**D.O. No. 1-6/2009-Desk (MDM)**  
**8<sup>th</sup> October, 2015**

Dear *Colleague,*

The Mid Day Meal Rules, 2015 have been notified under the National Food Security Act, 2013 and the same are effective from the date of its publication i.e. 30<sup>th</sup> September, 2015. Enclosed herewith is a copy of these MDM Rules for your ready reference. I wish to draw your special attention to the following Rules.

2. Rule 7 provides for the role of SMCs in monitoring of the MDM Scheme. Further, the Rule provides that Headmaster or Headmistress of the school shall be empowered to utilize any fund in the school temporarily for the purpose of continuation of the Mid Day Meal Scheme in the school.

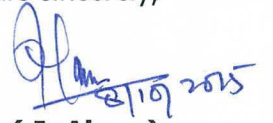
3. Rule 8 emphasizes on the quality of food to ensure that the meal meets the nutritional standards and quality prescribed by the MDM Rules. The Food and Drug Administration Department of the State may collect samples from randomly selected schools to ensure adherence to quality.

4. Rule 9 is about food security allowance to be paid by the State Government, if MDM is not provided in any school for three consecutive days or five days in a month. The State Government shall take action to fix responsibility on the person or agency in accordance with the procedure laid down.

5. These Statutory Rules will need to be disseminated and enforced in all eligible schools. Several of these rules would also be required to be backed by further detailed operational instructions. I shall request you to kindly take necessary action to operationalize these rules and lay down a set of instructions for their effective implementation in all the schools so as to ensure adherence to the changed norms for serving quality meals to children covered under Mid Day Meal Scheme.

With regards,

Yours sincerely,

  
( J. Alam )

**Encls.:** as above.

State Education Secretaries of all States/UTs  
and Secretaries of Departments implementing MDM in schools  
(As per list enclosed)





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2015/आश्विन 8, 1937

No. 599]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2015/ASVINA 8, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(कूल शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2015

**सा. का.नि. 743(ब).**- केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के धारा 39 के उप-धारा (2) के उपबंध (ख) के साथ पठनीय उप-धारा (1) के द्वारा दत्त शक्तिय का योग करते ए नि नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्याह्न भोजन नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परभाषाएं-** इन नियमों में, जब तक कि यथा संदर्भ से अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का अर्थ केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) से अभिहित है;

(ख) "खाद्य" से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज अथवा इनके मिश्रण से अभिहित है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के द्वारा अवधारित क्वालिटी से नियमों के अनुरूप होंगे;

(ग) "खाद्य सुरक्षा" से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को इस अधिनियम के धारा 8 के अधीन दिया गया खाद्य और धनराशि से अभिहित है;

(घ) "भोजन" से पके-पकाये गर्म भोजन से अभिहित है;

(ङ.) "कूल" सब शिक्षा अभियान के अधीन समर्थित मदरस और मकतब सहित स्थानीय निकाय, सरकार या सरकार की सहायता द्वारा चल रहे कोई कूल सम्मिलित हैं।

(च) "धारा" से इस अधिनियम के धारा अभिहित है; और

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें युक्त हैं और परभाषित नहीं हैं, कतु वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **पोषक भोजन के लिए पात्रता-** कक्षा I से VIII म अध्ययन वाले छह से चौदह वर्ष क आयु समूह के भीतर येक बालक, जो कूल म अ यावेशन करता है और उपथित होता है, को कूल अवकाश के दन को छोड़कर येक दन, अधिनियम क अनुसूची 2 म यथा-विनि द ट पोषक मानक वाला भोजन मुफ्त दया जाएगा।
4. **भोजन परोसने का थान-** भोजन केवल कूल म परोसा जाएगा।
5. **भोजन तैयार करना और मानक तथा वालिटी का अनुरण-** (1) भोजन क िय सरकार ारा समय-समय पर जारी मध्याह्न भोजन मार्गदर्शक सिद्धांत और इस अधिनियम क अनुसूची 2 म विनि द ट उपबंध के अनुसार तैयार कया जाएगा।
- (2) येक कूल म वच्छ रीति से भोजन पकाने क सुविधा होगी। शहरी क्षेत्र म थित कूल जहां कह अपेक्षित हो, क िय सरकार ारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार भोजन पकाने के लिए क िकृत पाकशाला संबंधी सुविधाओं का उपयोग कर सकते ह लेकिन बालक को भोजन केवल कूल म ही परोसा जाएगा।
6. **म या न भोजन क म के लिए रा य संचालन-सह निगरानी समिति-** मध्याह्न भोजन क म के लिए राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएसएमसी) अधिनियम का काया वयन सुनिचित करने के आशय से क म के काया वयन तथा भोजन के पोषक मानक और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए तंत्र क थापना क निगरानी करेगी।
7. **म या न भोजन योजना म कूल बंधन समिति (एसएमसी) क भूमिका-** (1) निःशुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन कूल बंधन समिति को यह दायि व स पा गया है क वह मध्याह्न भोजन क म के काया वयन क निगरानी करेगी और मध्याह्न भोजन क म के काया वयन म, बालक को दए जाने वाले भोजन क क्वालिटी, खाने पकाने के थान क साफ-सफाई और वच्छता बनाए रखने पर निरीक्षण रखेगी।
- (2) कूल का धानाध्यापक अथवा धानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा क वह कूल म खा ान, पकाने क लागत आ द अ थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले म मध्याह्न भोजन क म जारी रखने के योजन के लिए कूल म उपलब्ध निधि का उपयोग करे। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां ाति होते ही त काल कूल के खाते म उपयोग क गई धनराशि क तिपूर्ति कर दी जाएगी।
8. **यायित योगशाला ारा भोजन का परी ण-** (1) सरकारी खा अनुसंधान योगशालाएं अथवा विधि ारा यायित या मा यता ा त कोई भी योगशाला बालक को दए जाने वाले पके-पकाये गम भोजन का मूल्यांकन करेगी और इसे माणित करेगी, ता क यह सुनिचित कया जा सके क यह भोजन अधिनियम क अनुसूची 2 म विनि द ट पोषक मानक और क्वालिटी के अनुरूप हो। राज्य के खा और औषधि शासन विभाग भोजन का पोषक मूल्य और क्वालिटी सुनिचित करने के लिए इसके नमूने लगे।
- (2) उप-नियम (1) म नि द ट विभाग **गादृच्छक प से चुने गए कूल और क िकृत पाकशाला** से हर माह कम से कम एक बार नमूने एकत्र करेगे और इ ह उप-नियम (1) म नि द ट योगशालाओं को परीक्षण के लिए भेजेगे।
9. **खा सुर ा भ ता-** (1) य द खा ान, पकाने क लागत, ईंधन उपलब्ध न होने या रसोईया-सह-हे पर के अनुपथित रहने अथवा कसी अ य कारण से कसी भी कूल दन के कूल म मध्याह्न भोजन उपलब्ध नह कराया जाता है तो नियम 3 म नि द ट येक बच्चे को राज्य सरकार नियम 2 के उपबंध (ग) म यथा-प रभाषित खा सुरक्षा भ ता नीचे दए गए रीति से आगामी मास क 15 तारीख तक उपलब्ध कराएगी:-
- (क) बालक क पात्रता के अनुसार खा ान क मात्रा; और
- (ख) राज्य म उस समय अभिभावी खाना पकाने क लागत।
- (2) क िकृत पाकशाला ारा भोजन क आपूर्ति न करने के मामले म, क िकृत पाकशाला से उप-नियम (1) के अनुसार खा सुरक्षा भ ता वसूला जाएगा:
- परंतु य द कोई बालक उसे दया गया भोजन कसी भी कारण से नह लेता है, तो राज्य सरकार अथवा क िकृत पाकशालाओं से खा सुरक्षा भ ते का कोई दावा नह कया जाएगा:
- परंतु यह और क खा ान और भोजन क क्वालिटी के कारण के लिए राज्य सरकार अथवा क िकृत पाकशालाओं से कोई दावा नह कया जाएगा:
- (3) य द कूल दन म लगातार तीन दन तक अथवा एक मास म कम से कम पांच दन तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नह कराया जाता है, तो राज्य सरकार अभिकथित क्रयाओं के अनुसार यक्ति अथवा अभिकरण पर जि मेदारी नियत करने के लिए कारवाई करेगी।

(4) जहाँ कह भी क िय सरकार क कोई अभिकरण अंतव तत हो, रज्य सरकार इस मामले को क िय सरकार के साथ उठाएगी जो एक मास के अंदर इस मामले का समाधान करेगी।

10. **व्यावृति-** इन नियम म निहित बात, इसके पक्ष से जारी माग शक सिद्धत अथवा मध्याह्न भोजन क म से संबंधित काय लाप के क बारे म क िय सरकार ारा जारी कए जाने वाले संभा यत: को भावित नह करेगी।

[ फा. सं. 1-6/2009-डे क (एमडीएम)]

गया साद, निदेशक (मध्याह्न भोजन)

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2015

**G.S.R.743(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Mid-Day Meal Rules, 2015.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) “Act” means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
  - (b) “foodgrains” means rice, wheat, coarse grains or any combination thereof conforming to such quality norms as may be determined, by order, by the Central Government from time to time;
  - (c) “food security allowance” means the food grain and money to be paid by the concerned State Government to the entitled person under section 8 of the Act;
  - (d) “meal” means hot cooked meal;
  - (e) “School” includes any school run by Local Bodies, Government or aided by the Government including madrasas and maqtabas supported under Sarva Shiksha Abhiyan;
  - (f) “section” means the section of the Act; and
  - (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Entitlement for nutritional meal.** – Every child within the age group of six to fourteen years studying in classes I to VIII who enroll and attend the school, shall be provided meal having nutritional standards as specified in Schedule II of the Act, free of charge every day except on school holidays.
4. **Place of serving meal.** – The meal shall be served to children at school only.
5. **Preparation of meals and maintenance of standards and quality.** – (1) The meal shall be prepared in accordance with the Mid Day Meal guidelines issued by the Central Government from time to time and in accordance with the provisions of Schedule II of the Act.  
(2) Every school shall have the facility for cooking meal in hygienic manner. Schools in urban area may use the facility of centralised kitchens for cooking meals wherever required in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the meal shall be served to children at respective school only.
6. **State Steering-cum-Monitoring Committee for Mid-Day Meal Scheme.** – The State Steering-cum-Monitoring Committee (SSMC) shall oversee the implementation of the scheme with a view to ensure implementation of the Act including establishment of a mechanism for maintenance of nutritional standards and quality of meals.
7. **Role of School Management Committee (SMC) for monitoring Mid-day meals scheme.** – (1) The School Management Committee mandated under Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 shall also monitor implementation of the Mid-day meal Scheme and shall oversee quality of meals provided to the children, cleanliness of the place of cooking and maintenance of hygiene in implementation of mid day meal scheme.  
(2) The Headmaster or Headmistress of the school shall be empowered to utilise any fund available in school for the purpose of continuation of Mid Day Meal Scheme in the school in case of temporary unavailability of

food grains, cooking cost etc. in the school. The utilised fund shall be reimbursed to the school account immediately after receipt of mid day meal funds.

- 8. Testing of Meals by accredited Laboratories** – (1) Hot cooked meal provided to children shall be evaluated and certified by the Government Food Research Laboratory or any laboratory accredited or recognized by law, so as to ensure that the meal meets with the nutritional standards and quality specified in Schedule II to the Act. The Food and Drugs Administration Department of the State may collect samples to ensure the nutritive value and quality of the meals.
- (2) The Department referred to in sub-rule (1) shall collect the samples at least once in a month *from randomly selected schools or centralised kitchens* and send such samples for examination to the laboratories referred to in sub-rule (1).
- 9. Food Security Allowance.** - (1) If the Mid-Day Meal is not provided in school on any school day due to non-availability of food grains, cooking cost, fuel or absence of cook-cum-helper or any other reason, the State Government shall pay food security allowance as defined in clause (c) of rule 2 to every child referred to in rule 3 by 15<sup>th</sup> of the succeeding month in the manner provided herein below:-
- (a) Quantity of Food grains as per entitlement of the child; and
- (b) Cooking cost prevailing in the State.
- (2) In case of non-supply of meal by the Centralised Kitchen, the Food Security Allowance shall be realised from the Centralised Kitchen as per sub-rule (1):
- Provided that in case a child has not taken food on offer for whatever reasons, no claim of food security allowance shall lie with the State Government or Centralised Kitchens:
- Provided further that no claim shall lie with State Government or Centralised Kitchen for reasons of quality of food grains and meal:
- (3) The State Government shall take action to fix responsibility on the person or agency in accordance with the procedure laid down, if mid day meal is not provided in school on school days continuously for three days or at least for five days in a month.
- (4) Wherever an agency of Central Government is involved, the State Government shall take up the matter with Central Government which shall resolve the matter within a month.
- 10. Saving.** - Nothing in these rules shall affect the guidelines issued in this behalf or likely to be issued by the Central Government regarding the activities relating to Mid Day Meal Scheme.

[F. No. 1-6/2009-Desk(MDM)]

GAYA PRASAD, Director (Mid Day Meal)